(ii) जनजातीय क्षेत्रों में सभी एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाना ।

(iii) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में जो दूर संचार सुविधाएं देने का प्रस्ताव है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न नुसार है :--

क्र०सं०	मद	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	बिहार
1.	निवल स्थानीय स्विचन क्षमता	21150	52000	19100
2.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	14800	41700	18500
3.	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक		

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को अनुदान

744. **श्री अजीत जोगी** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 3 अक्तूबर, 1989 को केन्द्र सरकार के पास वर्ष 1989-90 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 92.83 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गये हैं ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा 500 व अधिक जनसंख्या वाले आदिवासी ग्रामों को सुरक्ष मार्गों से जोड़ने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति/वित्तीय सहायता हेतु भेजा है ;

(ग) मध्य प्रदेश शासन को उक्त राशि उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जायेगा और यह राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी, और

(घ) क्या 500 से कम जनसंख्या वाले आदिवासी गांवों को भी सड़कों से जोड़ने के बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री, साथ में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग को, जो कि नोडल मंत्रालय है, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि, वे आदिवासी ग्रामों को जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं चला रहे हैं ।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि, जिसके आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अभी नहीं हुई है, इसलिए इन प्रस्तावों पर अनमोदन के लिए कार्यवाही नहीं की गई है ।

(घ) जी, नहीं ।

मध्य प्रदेश में सड़क विकास के लिये विश्व बैंक सहायता

745. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार की इस वर्ष सडक विकास के लिये विश्व बैंक से कुल कितनी ऋण सहायता प्राप्त होने की संभावना है ;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकार किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

जल संसाधन मंत्री, साथ में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) 75.12 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर इन्दौर देवास खंड में 19.0 कि० मी० लम्बाई को चार लेन का बनाने तथा इन्दौर बाई पास (लम्बाई 31.4 कि० मी) के निर्माण के प्रस्ताव को संभावित सहायता के लिए विश्व बैंक के समक्ष पेश किया गया है । ऋण के लिए अभी विचार-विमर्श किया जाना है । अतः परियोजना के अनुमोदन की संभावित तारीख और व्यय के समय के बारे में कहना समयपूर्व है ।

दूसरे देशों में भारतीय वाणिज्य दूतावास

746. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन देशों में भारतीय वाणिज्य दूतावास कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उन दूतावासों द्वारा विशेष रूप से व्यापार आदि को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं ;

(ग) उन दूतावासों में नियुक्त अधिकारियों के नाम क्या हैं, साथ ही वे वहां कितनी-कितनी अवधि से हैं ?

विदेश मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) प्रमुख कोंसलावासों, कोंसलावासों तथा सहायक हाई कमीशनों (जो राष्ट्र-मंडल देशों में कोंसली कार्यालयों के पदनाम हैं) की सूची अनुपत्र में दी गई है जिसमें केन्द्रों तथा देशों का ब्यौरा भी है । **[देखिये** परिशिष्ट 156, अनुपत्र सं० 15]

(ख) भारत के प्रमुख कोंसलावास/कोंसलावास/सहायक हाई कमीशन अनिवार्य रूप से कोंसली कार्यालय हैं जिनसे उनके कोंसली अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रिकों तथा भारतीय मूल के लोगों के हितों और आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद की जाती है । जहां आवश्यक होता है भारत के प्रमुख कोंसलावासों/कोंसलावासों/सहायक हाई कमीशनों का इस्तेमाल उनके कोंसली प्रत्यावर्तन क्षेत्र में तथा प्रत्यावर्तन के देश में भारतीय राजदूत/हाई कमीशन के समन्वय से वाणिज्यिक, सांस्कृतिक तथा प्रचार कार्य करने के लिए भी किया जाता है । इस प्रकार व्यापार का संवर्धन भी भारत के प्रमुख कोंसलावासों/कोंसलावासों/सहायक हाई कमीशनों के कार्यों में शामिल है ।

(ग) वहां तैनात राजनयिक अधिकारियों की सूची केन्द्रों में उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख के साथ अनुबंध में दी गई है ।[**देखिये** परिशिष्ट 156, अनुपत्र सं० 15]

Irrigation projects in Tamil Nadu with Central Assistance

747.. SHRI R. T, GOPALAN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the number of irrigation projects undertaken wtih Central assistance under irrigation Development Programme ia Tamil Nadu during the Seventh Plan period; and

(b) the progress made and assistance given by the Central Government in this regard so far?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE